कैप्सूल
03

दृष्टि
The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

प्रश्नपत्र-III

आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

IAS/PCS की मुख्य परीक्षा के
संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तर शैली में कवरेज

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव / एस.डी. कार्ड / टैबलेट

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव तथा टैबलेट मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स या टैबलेट कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30–30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट–ऑफ–द–आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि
The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

प्रश्नपत्र–III

आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

Drishti Publications
dp

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण- नवंबर 2020

मूल्य : ₹ 280

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

आप सब यह जानते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में हम सफलता की दौड़ में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही शामिल हो पाते हैं। हालाँकि इस दौड़ में अंतिम विजय प्राप्त कर पाना मुख्य परीक्षा में हमारे प्रदर्शन पर बहुत हद तक निर्भर है। मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने से हम सफलता के नज़दीक तो पहुँचते ही हैं, साथ ही अंतिम परिणाम में रैंक निर्धारण में भी इसकी महती भूमिका है। अत: यह कहना उचित ही होगा कि मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन व सिविल सेवा में चयन लगभग समानार्थी हैं। इसी उद्देश्य को साधने हेतु हम अब 'मेन्स कैप्सूल सीरीज़' के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले जब हमने 'प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़' को शुरू किया था तो इसे आप पाठकों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ। साथ ही अनेक पाठकों का निवेदन भी प्राप्त हुआ कि इसी तर्ज़ पर हम मुख्य परीक्षा पर भी सामग्री उपलब्ध कराएँ। हमारी टीम पहले से इस दिशा में कार्य कर भी रही थी और अब यह मूर्त रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। हम इस सीरीज़ की कुछ बुनियादी बातों को आपसे साझा करना चाहेंगे और फिर विशिष्ट रूप से इस पुस्तक की चर्चा करेंगे।

सीरीज़ में कुल चार पुस्तकें होंगी जो क्रमश: सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्रों को संपूर्णता से कवर करेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये एक पृथक् पुस्तक होगी। इसे हमने प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया है। अब, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इन विषयों पर तो पहले से बहुत सामग्रियाँ हैं फिर इस सीरीज़ में खास क्या है? तो, ठीक बात है कि इन पर सामग्रियों की कोई कमी नहीं है लेकिन इन उपलब्ध सामग्रियों में जिस बात का घोर अभाव है, वो यह कि ये ठीक तरीके से लक्ष्य को संबोधित नहीं हैं। आपको बात थोड़ी जटिल लग रही होगी, इसलिये इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं। दरअसल, मुख्य परीक्षा में सफलता मूलत: दो तत्त्वों पर निर्भर करती है- एक सटीक उत्तर लेखन कौशल और दूसरा पूरे पाठ्यक्रम को बार-बार रिवाइज़ करना। अब अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है जो पूरे पाठ्यक्रम को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत करती हो तो आपके लिये बहुत मुश्किल है कि आप पढ़े हुए पाठ का सही उत्तर लिख पाएंगे। साथ ही, बार-बार रिवाइज़ करने के लिये आवश्यक है कि सामग्री बहुत विस्तृत और बिखरी हुई न हो। इन्हीं दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिये हमने 'मेन्स कैप्सूल सीरीज़' को शुरू किया है, ताकि प्रश्नोत्तर शैली में आप पूरे पाठ्यक्रम को देख सकें और संक्षिप्त व सटीक सामग्री को परीक्षा के पहले कई बार दुहरा सकें।

इस सीरीज़ की तीसरी कड़ी के रूप में 'आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन' प्रस्तुत है। इसमें हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो खंड परीक्षा के लिहाज़ से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और जिनसे अधिक प्रश्न पूछने का चलन रहा है, उनसे अधिकाधिक प्रश्न शामिल किये जाएँ। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस कसौटी का ठीक से अनुभव कर पाएंगे। उदाहरण के माध्यम से कहें तो अर्थव्यवस्था (आर्थिक विकास) से पूछे जाने वाले प्रश्नों की विविधता को देखते हुए उन सभी हिस्सों को ठीक से कवर किया गया है, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, यथा- कृषि, परिवहन। पर्यावरण व प्रौद्योगिकी खंडों में पारंपरिक और गतिशील तत्त्वों को रेखांकित करते हुए प्रश्नोत्तर तैयार किये गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में आपसे प्रश्न छूटने न पाए, साथ ही इनमें भी अधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सों, यथा-पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन व प्रौद्योगिकी में रोबोटिक्स को बेहतर कवरेज दी गई है। आपदा प्रबंधन के खंड को हमने इस अप्रोच से शामिल किया है कि उसका पूरा ही पाठ्यक्रम आपकी नज़रों से गुज़र जाए। इसी प्रकार कहें तो सुरक्षा खंड में हालिया घटनाक्रम से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। ये सामग्रियाँ अपने आप में पर्याप्त हैं तथा आपको इसके लिये अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। खासकर जब आप पाठ्य-सामग्री को प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और सटीकता से संपन्न होगी।

प्रश्नोत्तर शैली में एक चुनौती यह भी थी कि प्रश्नों को किस प्रकार से आकार दिया जाए कि वे यूपीएससी के मानक के अनुकूल भी हों और जिनसे पाठ्यक्रम भी संपूर्णता से शामिल हो जाए। हमारी टीम, जिसके सभी सदस्य इस परीक्षा का लंबा अनुभव रखते हैं, ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर अंतत: एक कामयाब संतुलन साधा जा सका। पुस्तक से गुज़रते हुए आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। इस सीरीज़ से आपको एक लाभ यह भी होगा कि आप अपने उत्तर लेखन की कला को बेहतर बना पाएंगे। सीमित शब्दों में कैसे पूरी बात कही जा सकती है, इसे सीखने में यह पुस्तक आपकी पूरी मदद करेगी।

आप निश्चिंत होकर इस सीरीज़ को अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी का आधार बना सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इससे आपकी सफलता की संभावना प्रबल होगी। फिर, अगर आप इस पुस्तक के बारे में अपनी कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो **8130392355** नंबर पर वाट्सएप करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।

शुभकामनाओं सहित...
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-1 1-130

आर्थिक विकास

खंड-2 131-166

पर्यावरण

खंड-3 167-220

प्रौद्योगिकी

खंड-4 221-270

सुरक्षा

खंड-5 271-292

आपदा प्रबंधन

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र-III

खंड-1

आर्थिक विकास

ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है? क्या ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुधार कोविड-19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकता है? तार्किक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Why is the rural sector important for the economy? Can economic reforms in the rural sector speed up the economy after Covid-19? Logically analyze.

उत्तर: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 68.8 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 46 प्रतिशत है। इस संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोविड-19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में महत्त्व

- देश में कुल निर्माण गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है।
- देश में कुल सेवा उत्पादन में एक चौथाई योगदान ग्रामीण क्षेत्र का है।
- देश का आधे से अधिक औद्योगिक उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों से आता है।
- वहीं दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार में लगे 20 प्रतिशत से अधिक परिवारों की आय गरीबी रेखा के स्तर से कम है।
- शहरी क्षेत्र की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र भी विदेशी वस्तुओं के शुद्ध आयातक हैं जो धन के बाह्य प्रवाह का कारण है।

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुधार से कोविड-19 के पश्चात अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

- पशुधन, मछली पालन, डेयरी, सब्ज़ियाँ, फल और खाद्य प्रसंस्करण अधिक श्रम-गहन और उच्च मूल्य-उपज वाले व्यवसाय हैं। हाल के आर्थिक सुधारों में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो अधिशेष श्रम को नियोजन प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन कर सकते हैं।
- माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) की औपचारिकता के लिये ₹10,000 करोड़ की योजना घोषित की गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।
- ग्रामीण साख समितियों और स्थानीय सामुदायिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन के लिये स्थानीय बुनकर, कारीगर और शिल्पकार को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यम को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये पहल करने से रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रिकॉर्ड रोज़गार प्रदान किया गया था। इस वर्ष मनरेगा का बजट ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह में वृद्धि होगी।

विविध आर्थिक सुधारों से ग्रामीण क्षेत्र में आय का स्तर बढ़ सकता है तथा इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। इसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का सुचक्र बेहतर होगा तथा अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्राप्त होगी।

वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये निरंतर नीतिगत सुधार, कर सुधार, अवसंरचना निर्माण और साख उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

'वोकल फॉर लोकल' से क्या आशय है? क्या यह भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं करेगा? स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

What does 'Vocal for Local' mean? Will it not detach India from the global economy? Explain.

उत्तर: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान राहत पैकेज की घोषणा करते हुए 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र दिया था। इसके साथ ही उन्होंने "आत्मनिर्भर भारत" का लक्ष्य निर्धारित किया था।

कोविड-19 के कारण विश्व स्तर पर कई देशों में लॉकडाउन से आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम करके घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति पर बल दिया जा रहा है। वास्तव में 'वोकल फॉर लोकल' की रणनीति सरकार की 'मेक इन इंडिया' योजना को सुदृढ़ करने की तरह ही है। जहाँ 'मेक इन इंडिया' ने आपूर्ति पक्ष सुधारों को लाने का प्रयास किया था, वहीं इसके तहत मांग पक्ष में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की रणनीति के

खंड–2

पर्यावरण

सीबैड 2030 प्रोजेक्ट क्या है? इसका जलवायु परिवर्तन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में महत्त्व की चर्चा कीजिये व यह स्पष्ट कीजिये कि संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-14 को पूरा करने में यह कैसे अहम भूमिका निभा सकता है? (250 शब्द) 15

What is the Seabed 2030 Project? Discuss its importance in the study of climate change and other natural calamities and explain how it can play a vital role in achieving United Nation's Sustainable Development Goal-14?

उत्तर: 'सीबैड 2030' प्रोजेक्ट जापान के निप्पन फाउंडेशन और महासागरों के जनरल बाथिमेट्रिक चार्ट (GEBCO) के बीच एक सहयोगी परियोजना है। इसका उद्देश्य 2030 तक विश्व महासागर तल का एक निश्चित (Definitive) मानचित्र का निर्माण करने के लिये सभी उपलब्ध बाथिमेट्रिक आँकड़ों को संग्रहीत करना एवं इसे सभी के लिये उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट को जून 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) में शुरू किया गया था। जून 2020 तक इस प्रोजेक्ट का पाँचवा हिस्सा पूरा किया जा चुका है अर्थात् संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के 1/5 भाग की मैपिंग की जा चुकी है।

कई वर्षों के प्रयास के बावजूद दुनिया के समुद्र के 20 प्रतिशत से भी कम भाग को ही मानचित्रित किया गया है। सीबैड 2030 सभी मौजूदा आँकड़ों को एक साथ संगृहीत करने और भविष्य के सर्वेक्षणों के लिये क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एवं "मैप्स द गैप" (Maps the Gap) को पूरा करने के लिये एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह प्रयास जरूरी भी था क्योंकि समुद्र के बारे में हमारे कई मौलिक प्रश्न जैसे–वैश्विक महासागरीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाला हिमनद बर्फ कैसे पिघलता है? जल के नीचे कितना इतिहास है जिससे हम अनभिज्ञ हैं? ऐसे और कई प्रश्नों के जवाब जानने में सीबेड 2030 प्रोजेक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं तथा आज के मौसम से लेकर जलवायु में दशकों-लंबे बदलावों को समझने में लगे हुए हैं। चूँकि पृथ्वी पर महासागर हावी है तथा समुद्र की ताप क्षमता वायुमंडल के लगभग 1000 गुना है, इसलिये वैश्विक तापन का सीधा संबंध महासागरीय तापन से है जो अंततः जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है।

वैश्विक महासागरीय परिसंचरण को पूरी तरह से बेहतर बाथिमेट्री (Bathymetry) के बिना नहीं समझा जा सकता। बाथिमेट्री के माध्यम से महासागर के तल के आकार व गहराई की माप, समुद्रों या महासागरों में मौजूद जल की गहराई के स्तर की माप एवं जल के नीचे स्थलाकृति के आकार के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। ये मानचित्र महत्त्वपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ विकसित करेंगे, क्योंकि कैनियन, अंतर्जलीय ज्वालामुखी एवं सतही विशेषताएँ समुद्री जल के ऊर्ध्वाधर मिश्रण एवं समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं–जो गर्म एवं ठंडे पानी के कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करती हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन धाराओं को भी प्रभावित किया है। चूँकि समुद्री धाराएँ मौसम एवं जलवायु दशाओं को प्रभावित करती हैं अतः समुद्री धाराओं के बारे में प्राप्त अधिकाधिक जानकारी वैज्ञानिकों के लिये भविष्य में जलवायु के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल विकसित करने में सहायक होगी, जिसमें समुद्र तल की वृद्धि भी शामिल है। इसके साथ ही यह मानचित्रण समुद्र के संचलन, ज्वार एवं जैविक आकर्षण के केंद्र सहित कई प्राकृतिक घटनाओं एवं आपदाओं (जैसे– समुद्री भूकंप, सुनामी एवं चक्रवात) को समझने में सहायक है। आपदा स्थितियों का आकलन करने के लिये भी समुद्र तल का अध्ययन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2011 में जापान के तोहोकू में आए विनाशकारी भूकंप के पीछे के कारणों का पता लगाने में वैज्ञानिकों द्वारा समुद्री अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया था।

चूँकि सीबेड 2030 का महासागरों, समुद्रों व समुद्री संसाधनों के संरक्षण और निरंतर उपयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-14 के साथ भी गठबंधन है इसलिये इस प्रोजेक्ट के द्वारा सतत् विकास-लक्ष्य-14 को भी पूरा करने में काफी मदद मिल सकती है। सीबेड 2030 के माध्यम से संसाधन अन्वेषण (उदाहरण के लिये तेल, गैस और खनिज), मत्स्य प्रबंधन एवं अपतटीय पवन टर्बाइन के निर्माण आदि के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी साथ ही इसके माध्यम से विश्व को समुद्री संसाधनों के बारे में नीतिगत निर्णय लेने, महासागर की सही स्थिरता की जानकारी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संबधित गतिविधियों नई दिशा मिल सकेगी।

भारत को भारत स्टेज–IV (बीएस–IV) से बीएस–VI तक लीपफ्रॉग की आवश्यकता क्यों पड़ी? बीएस–IV व बीएस–VI का तुलनात्मक वर्णन करते हुए बीएस–VI के फायदों की चर्चा कीजिये तथा बीएस–IV से बीएस–VI में स्थानांतरण में ओईएम के समक्ष उत्पन्न प्रौद्योगिकी चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

Why did India need to leapfrog from Bharat Stage-IV (BS-IV) to BS-VI? Comparatively describing BS-IV and BS-VI, discuss the advantages of BS-VI and specify challenges risen in front of OEM during the transformation from BS-IV to BS-VI.

उत्तर: भारत स्टेज VI (बीएस VI) एक ऑटोमेटिव उत्सर्जन मानक है जो भारत सरकार द्वारा वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिये निर्धारित किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएँ को नियंत्रित करना है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इस उत्सर्जन मानदंड के लागू हो जाने के बाद भारत अमेरिका, यूरोपीय देशों और दुनिया भर के अन्य उन्नत ऑटोमेटिव बाज़ारों के बराबर आ जाएगा।

खंड–3

प्रौद्योगिकी

भारत का दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है जो भारत में 5G तकनीक के प्रयोग के समक्ष भी अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। इन चुनौतियों की चर्चा करते हुए इनके समाधान हेतु उपायों को बताएँ। (250 शब्द) 15

India's telecom sector is currently plagued with many problems which also pose many challenges before the use of 5G technology in India. Discussing these challenges, suggest ways to solve them.

उत्तर: 5G अगली पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ तेज़ और अधिक विश्वसनीय संचार सेवाएँ प्रदान करेगी। सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G के साथ पीक नेटवर्क डेटा स्पीड 2–20 जीबी प्रति सेकेंड की सीमा में होने की संभावना व्यक्त की गई है।

वर्ष 1994 में दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण हुआ किंतु निजी क्षेत्र का इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सका। वर्ष 1999 में सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई, जिसके बाद यह क्षेत्र राजस्व शेयर लाइसेंस शुल्क प्रणाली की ओर बढ़ तो गया लेकिन वर्तमान समय में भी यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

विनियामक से जुड़ी अनिश्चितता एवं स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी के कारण भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में 5G तकनीक आरंभ होना अभी शेष है। दूरसंचार क्षेत्र गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, साथ ही 5G तकनीक प्रयोग हेतु आधारभूत संरचना एवं नए उपकरणों का भी अभाव है। टेलिकॉम कंपनियों के मध्य बढ़ती अनुचित प्रतिस्पर्धा से इस राह में और देरी हुई है।

दुनिया के लगभग सभी विकासशील देश 5G तकनीक को विकसित करने की होड़ में लगे हुए हैं। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन तथा चीन जैसे देश 5G सेवाओं की शुरूआत कर चुके हैं। ऐसे में भारत के दूरसंचार क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु कुछ उपाय निम्न हैं–

- वर्तमान टैरिफ प्रणाली को अधिक व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है ताकि दूरसंचार क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सशक्त बन पाएँ।
- कंपनियों के मध्य निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिये।
- दूरसंचार विभाग की कार्यशैली में विद्यमान अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिये, जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम परीक्षण का आबंटन किया जाना चाहिये।

ध्यातव्य है कि 5G भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है, इसके साथ ही चीन के बाद भारत मोबाइल इंटरनेट का दूसरा बड़ा बाज़ार भी है। वैश्विक दूरसंचार उद्योग निकाय-जीएसएमए के एक अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 920 मिलियन हो जाने की संभावना है, जिसमें लगभग 88 मिलियन उपभोक्ता 5G कनेक्शन वाले हो सकते हैं। निष्कर्षत: उपर्युक्त समस्याओं का समाधान कर भारत इस राह में आगे बढ़ सकता है।

नोट–'लेटेंसी' नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट द्वारा लिये गए कुल समय को लेटेंसी कहते है। यह समय अंतराल या देरी को संदर्भित करता है।

'आयुष चिकित्सा पद्धति को भविष्य की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का दर्जा दिया गया है।' कथन के आलोक में भारत सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12½

AYUSH treatment system has been given the status of alternative medicine method of the future. In light of the statement, discuss the steps taken by the Government of India to promote it.

उत्तर: आयुष चिकित्सा पद्धति से अभिप्राय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से है। आयुष को एलोपैथिक की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है। कम लागत वाली पद्धति होने के कारण यह बड़ी संख्या में देश के नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने की भी क्षमता रखती है। भारत को 'आयुष' चिकित्सा पद्धति में अतुलनीय विरासत प्राप्त है।

A	Y	U	S	H
आयुर्वेद	योग	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी

यह वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं में विद्यमान अंतराल को समाप्त करेगी, सुदूर क्षेत्रों में कम लागत वाली सेवाएँ प्रदान करेगी। इसके द्वारा मधुमेह, उच्च रक्त चाप, थॉयराइड, आर्थराइटिस एवं अन्य बीमारियों का बिना किसी दुष्प्रभाव के प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इसके साथ ही योग के माध्यम से तंबाकू एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

उपरोक्त लाभों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने हेतु कई प्रयास किये गए हैं–

- भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष देश में आयुर्वेद दिवस, यूनानी दिवस और सिद्ध दिवस मनाए जाते हैं। 190 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा 35 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है।
- वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आयुष मंत्रालय ने विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में सहयोग के क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- आयुष प्रणालियों के संवर्द्धन और विकास के लिये भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' को क्रियान्वित कर रही है।

- एक डी.एन.ए. स्ट्रैंड जब टूटा हुआ होता है तो उसमें खुद को ठीक करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस स्वयं से ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक हस्तक्षेप करते हुए आनुवंशिक कोड के वांछित अनुक्रम को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो खुद को टूटे हुए डी.एन.ए. स्ट्रैंड के साथ बाँधता है।

क्रिस्पर कैस-9 एक सरल, प्रभावी और अविश्वसनीय रूप से सटीक तकनीक है, जो भविष्य में मानव अस्तित्व में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। यद्यपि नैतिक चिंताएँ तब उत्पन्न होती हैं, जब जीनोम संपादन का उपयोग मानव जीनोम को बदलने के लिये किया जाता है।

बिग डेटा से आप क्या समझते हैं? शासन के संबंध में इसके कुछ अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये। (200 शब्द) 12½

What do you understand by big data? Mention its some applications in the field of governance.

उत्तर: बिग डेटा किसी संगठन द्वारा एकत्रित ऐसा संरचित, अर्द्धसंरचित एवं असंरचित डेटा का संयोजन है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग, भावी सूचक प्रतिरूपण एवं अन्य उन्नत अनुप्रयोगों आदि के लिये किया जाता है। बिग डाटा में पाँच मुख्य अवधारणाएँ शामिल हैं: आयतन, विविधता, वेग, मूल्य और सत्यता।

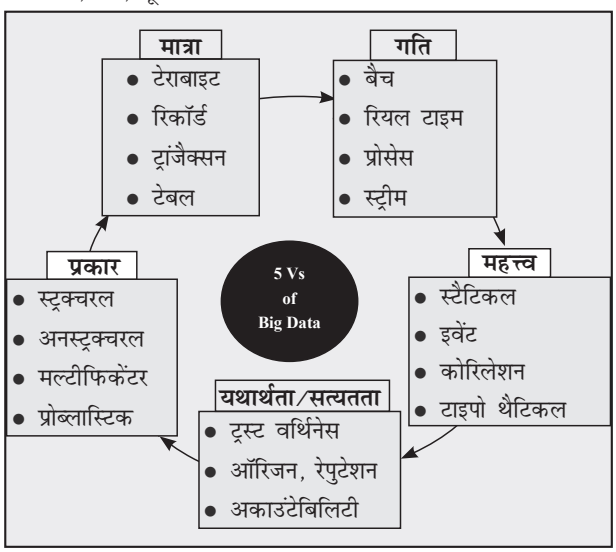

ई-गवर्नेंस में बिग डाटा विश्लेषण के अनुप्रयोग

एक बिग डाटा मंच (प्लेटफॉर्म) स्थापित कर सरकार अपने दैनिक कार्यों के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी की व्यापक मात्रा वास्तविक समय में उपलब्ध कर सकती है। यह सरकार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनके प्रयासों को इंगित करने की अनुमति देता है।

ऐसे क्षेत्र जहाँ बिग डाटा शासन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं-

- **परिवहन:** कार धारकों की संख्या से लेकर मौसम की स्थितियों तक परिवहन का प्रबंधन होता है। बिग डाटा के साथ सरकारें बेहतर और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करके मेट्रो और बसों सहित सार्वजनिक परिवहन के लिये योजना बना के बेहतर परिवहन सुनिश्चित कर सकती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** सरकार देश भर में चिकित्सा डाटा रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर सकती है और अपेक्षित लाभार्थियों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों और सेवाओं का व्यापक रूप से प्रबंधन कर सकती है।
- **कृषि:** कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिये बेहतर तकनीकों की आवश्यकता है। नीति आयोग ने आई.बी.एम. के साथ फसल उपज उत्पादनों के लिये एक मॉडल विकसित करने के लिये एक समझौता किया था। यह मॉडल ए.आई. का उपयोग करने जा रहा है और यह किसानों को वास्तविक समय की सलाह देने में मददगार साबित होगा।
- **काले धन का उन्मूलन:** सरकार ने कर चोरों को पकड़ने के लिये 2017 में प्रोजेक्ट इनसाइट नामक एक परियोजना शुरू की थी। परियोजना ने डाटा खनन तकनीकों का लाभ उठाया और भ्रष्टाचार मुक्त देश के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये डाटा का विश्लेषण किया। सरकार ने बड़े आकार के काले धन जमा वाले खातों को चिह्नित करने के लिये भी बिग डाटा का लाभ लिया है।
- **माल का प्रवाह और लोगों की आवाजाही:** अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का आकलन करने के लिये सरकार जीएसटी नेटवर्क के डाटा का उपयोग करती है। इसी तरह हर साल देश भर में प्रवासित लोगों की संख्या पर नज़र रखने के लिये, सरकार अनारक्षित रेल यात्रियों के डाटा का उपयोग करती है।
- **जल आपूर्ति:** केरल जल प्राधिकरण (के.डब्ल्यू.ए.) राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम् में जल के वितरण का विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन करने के लिये आई.बी.एम. के वैश्लेषिकी और गतिशीलता समाधानों का उपयोग कर रहा है। बिग डाटा वैश्लेषिकी तंत्र की मदद से आई.बी.एम., के.डब्ल्यू.ए. द्वारा निगरानी किये गए डाटा पूरे शहर में पानी के मीटर पर नज़र रख रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है।
- **बेहतर शासन और नीति निर्माण:** बिग डाटा विश्लेषण का उपयोग करके सरकार में प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन की निगरानी के लिये एक वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली तैयार की जा सकती है। यह नागरिकों के डाटा को समझने, सरकार के खर्च करने, उपभोग रुझान और विभिन्न सरकारी नीतियों की सफलता पर योजना तैयार करने में मददगार हो सकता है।
- **साइबर सुरक्षा:** बिग डाटा इंटरनेट के उपयोग में अनियमितताओं की जाँच करने, अवलोकन करने और उनका पता लगाने में मदद करता है। इस प्रकार सरकार आधार जैसे संवेदनशील डाटा को साइबर खतरों से बचाने के लिये इसका उपयोग कर सकती है।

विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में बिग डाटा वास्तव में मददगार हो सकता है, यदि डेटा या रिकॉर्ड का विश्लेषणपूर्वक और सावधानी से उपयोग किया जाए। हालाँकि खुले डाटा की उपलब्धता से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार को ऐसी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिये उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

खंड–4

सुरक्षा

"यूएपीए जैसे कानून के माध्यम से केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लगभग अनियंत्रित शक्ति समाहित कर ली है और इस प्रकार राज्य द्वारा उसके नागरिकों पर प्रभुता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। राज्य का नियामक की भूमिका त्याग कर नियंत्रक की भूमिका में आ जाना अपने आप में चिंताजनक स्थिति है।" कथन के आलोक में यूएपीए से उपजने वाले मुद्दों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

"The central government has assumed an uncontrolled amount of power in its hands through laws like UAPA and thus an attempt to establish dominance over its citizens has been made by the state.The state giving up the role of a regulator and assuming the role of a controller is worrying in itself." Critically analyze the issues arising out of UAPA in light of the statement.

उत्तर: भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से 1967 में संसद द्वारा 'विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967' पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य भारत की एकता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित कृत्यों की रोकथाम के लिये सरकार को प्रभावी शक्तियाँ उपलब्ध कराना है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों पर इस अधिनियम की धारा 35 के तहत रोक लगाई जाती है और अब 2019 में हुए एक संशोधन के बाद इस सूची में व्यक्ति भी शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि 2004 में एक संशोधन द्वारा इसमें आतंकवाद विरोधी प्रावधान भी शामिल किये गए। इसके बाद इसमें 2008 व 2013 में दो और संशोधन लागू किये गए।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न समयों पर अधिनियम में किये गए महत्त्वपूर्ण बदलावों के बाद अधिनियम को और कठोर बना दिया गया है, जिससे कि इन कानूनों के प्रति चिंताओं में वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी चिंता यूएपीए में 2019 में जोड़े गए 'व्यक्ति' को आतंकवादी का दर्जा देने के प्रावधान से संबंधित है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाने तक उसे निर्दोष माने जाने के तर्कपूर्ण विधिक सिद्धांत के सीधे विरोध में है। यहाँ सवाल उठता है कि जो देश मीसा, पोटा व टाडा जैसे कानून और उनका अनुपातविहीन दुरुपयोग देख चुका है, ऐसे में क्या एक और बहुत कठोर विधि बनाकर पुन: दुरुपयोग की आशंका के बादल उत्पन्न करना उचित या आवश्यक है? एक और गंभीर चिंता इस बात की है कि अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार चाहे तो असहमति को आतंकवादी विचारधारा का प्रसार कहकर दबा सकती है। ऐसे में देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी संकट मंडराता दिखाई देता है। एक अन्य चिंता इस बात की है कि ये दोनों कानूनों के सम्मिलित प्रभावस्वरूप एनआईए की शक्तियों में काफी वृद्धि हुई है। एजेंसी को पहले से ही प्रदत्त शक्तियाँ भारत की संघात्मक संरचना के विरोध में प्रतीत होती हैं और इन शक्तियों में और बढ़ोतरी से इस तरीके के सवाल और प्रखरता से उठेंगे।

हालाँकि इन सभी चिंताओं के बावजूद यह समझना ज़रूरी है कि भारत लगभग पिछली आधी सदी से 'ढाई मोर्चे के युद्ध' की आशंका से जूझ रहा है। इसका आशय यह है कि भारत को हर समय उत्तर व पश्चिमी मोर्चों पर पारंपरिक युद्ध लड़ने व इसी के साथ आंतरिक विद्रोहों को भी नियंत्रित करना होगा। ऐसे में हर मोर्चे पर विजयी होने के लिये सरकार को कुछ बेहद कठोर कानूनों की आवश्यकता होगी। चाहे ये कानून प्रथम दृष्टया राज्य का बढ़ता नियंत्रण क्यों न लगे पर यह अंतिम रूप से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक व्यवहार्य विकल्प है। इतने कठोर कानूनों से कुछ चिंताएँ उपजना स्वाभाविक है। लेकिन यह माना जा सकता है कि भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र ये कानून आवश्यक हैं। यद्यपि यह सुनिश्चित करना एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि यूएपीए जैसे कानूनों का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो सके, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे।

बोडो समस्या को संक्षेप में समझाते हुए हाल ही में हुए बोडो समझौते के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Explaining the Bodo issue in brief, discuss the major provisions of recently concluded Bodo Accord.

उत्तर: पूर्वोत्तर भारत का उल्लेख करते ही विहंगम भौगोलिक परिदृश्य व अद्भुत जनजातीय-सांस्कृतिक विविधता के चित्र दिमाग में कौंधते हैं। हालाँकि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ऐसी भौगोलिक व सांस्कृतिक धरोहर से सज्जित पूर्वोत्तर भारत कई हिंसक संघर्षों की भी भूमि रहा है। भारत सरकार निरंतर इन संघर्षों का लोकतांत्रिक दायरे में समाधान करने के प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में 27 जनवरी, 2020 को भारत सरकार, असम व असम के बोडो आंदोलन में शामिल सभी गुटों (NDFB के विभिन्न धड़े) ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह माना जा रहा है कि इस नवीन 'बोडो समझौते' पर हस्ताक्षर के बाद असम की 5 दशक से अधिक पुरानी बोडो समस्या का अंत होगा।

बोडो असम राज्य के सबसे आरंभिक निवासियों में से एक नृजातीय व भाषायी समुदाय है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बोडो बाहुल्य क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में अप्रवासियों के आकर बसने को बोडो समुदाय ने अपनी संस्कृति, सभ्यता, कला आदि पर खतरे की तरह देखा। बोडो समुदाय के लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार वर्ष 1966-67 में 'प्लेंस ट्राइबल कौंसिल ऑफ असम' नामक राजनीतिक संगठन के माध्यम से अपने लिये अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की थी। 1985 के असम समझौते के बाद 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन (ABSU) ने एक बार फिर पृथक् बोडोलैंड की मांग तेज़ की और असम राज्य को दो बराबर हिस्सों में बाँटने की मांग रखी। इसके बाद 1993 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ पहला बोडो समझौता

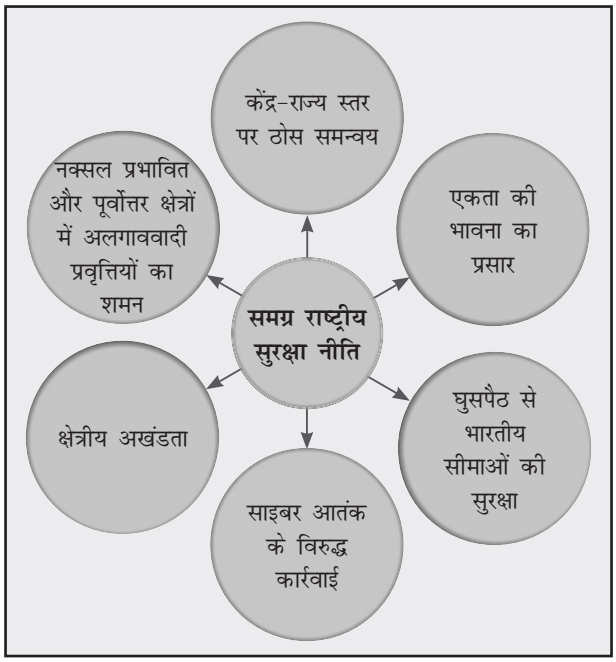

समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्मित करने के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क महत्त्वपूर्ण हैं-

- ऐसे कई राज्य हैं जो प्रभावी इंटेलिजेंस एजेंसी निर्मित करने में सक्षम नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य आंतरिक सुरक्षा पर खतरे जैसी आपद स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त और प्रशिक्षित पुलिस बल की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं। इसके लिये उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
- इस दिशा में सहकारी संघवादी विशेषता को प्राथमिकता मिल सकती है।

हालाँकि सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास ज़रूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति (Defence Planning Committee) की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले।

जब खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अवसंरचनागत विकास आदि के लिये नीतिगत व्यवस्थाएँ की गई हों तो आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय के लिये भी 'समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति' की ओर कदम बढ़ाना एक सार्थक कदम होगा।

संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? संगठित अपराध एवं आतंकवाद एक-दूसरे से कैसे अंतर्संबंधित हैं? स्पष्ट करें। भारत की आंतरिक सुरक्षा को इससे संभावित खतरों का उल्लेख करें। (150 शब्द) 10

What do you understand by organized crime? How organized crime and terrorism are interrelated? Explain. Discuss its potential as a threat to internal security of India.

उत्तर : 'संगठित अपराध', आपराधिक कृत्यों को सांगठनिक स्तर पर अंजाम देने की श्रेणी में आता है। इसके लिये आपराधिक तत्त्व केन्द्रीकृत मशीनरी निर्मित करते हैं और उपद्रव करने के लिये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर इस मशीनरी का उपयोग करते हैं। संगठित अपराध में सामूहिक गतिविधियों को वरीयता देकर योजनाबद्ध तरीके से अराजक तत्त्व भागीदारी निभाते हैं।

संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है-

सहयोग	सह-अस्तित्व	समायोजन अथवा एकीकरण
आतंकी समूह एवं आपराधिक समूह द्वारा एक-दूसरे के सहयोग से किसी योजना को अंजाम देना	आतंकी समूह एवं आपराधिक समूह द्वारा एक ही स्थान पर लेकिन अलग-अलग गतिविधियों में सक्रियता	दोनों समूहों का एक निकाय में ही परिवर्तित होकर काम करना

इस प्रकार दोनों ही पारस्परिक संबंध विकसित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अत: इन दोनों का गठजोड़ शासन-तंत्र के लिये नुकसानदेह हो सकता है।

इस गठजोड़ के निम्नलिखित परिणाम दिख सकते हैं-

- काले धन को वैध बनाने की कोशिश
- जाली मुद्रा का प्रसार
- हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना
- किसी क्षेत्र-विशेष की जनता पर राजनीतिक नियंत्रण आदि।

उल्लेखनीय है कि संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध वैश्विक परिदृश्य के साथ-साथ भारत में भी उपस्थित है:

- **कश्मीर में :** यहाँ संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच एक कड़ी नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार से जुड़ी है। यहाँ आतंकवादी नकली भारतीय मुद्रा को लाने के बड़े माध्यम हैं।
- **पूर्वोत्तर राज्यों में :** इस क्षेत्र में पनपे संगठित अपराधियों को शह देने के लिये सीमापार से मौद्रिक और हथियार सहायता मुहैया कराना। आतंकी संगठनों द्वारा सरकारी अधिकारियों को डरा-धमकाकर इनके पसंदीदा व्यक्तियों को सरकारी ठेके देने के लिये मजबूर किया जाता है।

इस प्रकार इन दोनों से समग्र रूप से निपटना नीति-नियंताओं के लिये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन दोनों से निपटने के लिये निम्नलिखित सुझाव महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं-

- साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को महत्त्व देते हुए गुप्तचर व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना।
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच के गठजोड़ को तोड़ने के लिये सूचना और निगरानी तंत्र विकसित करना।

खंड–5

आपदा प्रबंधन

हाल ही में विश्व के अनेक क्षेत्रों में 'टिड्डियों की आपदा' ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक चिंता पैदा की है। इसकी गंभीरता को बताते हुए इससे निपटने हेतु विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Recently in many areas of the world, a 'locust disaster' has caused widespread concern in the international community. Explaining its seriousness, discuss the steps taken by various countries to deal with it.

उत्तर: टिड्डी तृणभोजी (Grass hoppers) परिवार के कीड़े हैं जो उड़ने की अतुलनीय क्षमता रखते हैं। ये विभिन्न प्रकार की फसलों, पेड़-पौधों एवं चारों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक सक्रिय होते हैं इसलिये इन्हें मार्च-अप्रैल से अक्टूबर तक आसानी से देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर टिड्डियों की 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से डेजर्ट टिड्डे (Schistocerca Gregaria) को दुनिया में सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है। इसका कारण है कि ये अत्यधिक गतिशील होते हैं तथा लाखों टिड्डियों के झुंड बना सकते हैं, जिसके कारण विनाशकारी प्रभाव पैदा होते हैं। वर्ष 2019-2020 में टिड्डियों ने हार्न ऑफ अफ्रीका, मध्य पूर्व व दक्षिण एशिया में भारी खतरा पैदा कर दिया है जिसे वैश्विक समुदाय एक आपदा के रूप में देखती रहा है।

वर्ष 2019 की शुरुआत में टिड्डियों का पहला दल यमन, सउदी अरब से ईरान पहुँचा। इससे नए दलों की उत्पत्ति हुई जो वर्ष 2019 के अंत तक कीनिया, जिबूती एवं इरीट्रिया तक पहुँच गए जहाँ से ये विश्व के अन्य देशों की ओर बढ़ते गए। एशिया में ये मुख्यत: चीन, पाकिस्तान एवं भारत में खतरा बनकर आए। पाकिस्तान में टिड्डी दल ने भयंकर तबाही मचाया जिसके कारण पाकिस्तान को इसे 'टिड्डियों की राष्ट्रीय आपदा' घोषित करना पड़ा। भारत में टिड्डी दल ने पाकिस्तान के बलुचिस्तान, पंजाब एवं सिंधु प्रांत से प्रवेश किया। इसने भारत के अनेक राज्यों में फसलों को तबाह कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक एक औसत टिड्डी दल ढाई हज़ार लोगों का पेट भरने लायक अनाज एक दिन में चट कर सकता है। व्यापक पैमाने पर नियंत्रण के बिना व्यापक पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र, जिबूती और यमन जैसे देशों के लिये 8.5 बिलियन डॉलर की अनुमानित फसल, पशुधन उत्पादन और परिसंपत्ति क्षति सहित टिड्डी संबंधी नुकसान हो सकता है। ये टिड्डी प्रकोप लंबी वर्षा ऋतु के दौरान और भी व्यापक हो जाते हैं जब किसान अपने फसलों की कटाई की तैयारी करते हैं। इस प्रकार की स्थिति आने वाले महीनों में उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही समुदायों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है जो बचत, पुनर्निर्माण और फसलों व पशुधन के विकास और भविष्य के मौसमी झटकों को प्रभावित करते हैं।

'टिड्डियों की आपदा' से निपटने के लिये विभिन्न देशों ने अपने-अपने स्तर पर अनेक प्रयास किये हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसके रोकथाम हेतु चेतावनी, अलर्ट, स्थान एवं प्रजनन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये 'डेजर्ट लोकस्ट इंफॉर्मेशन सर्विस' को प्रारंभ किया है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का हवाई जहाजों, ट्रैक्टरों आदि के माध्यम से छिड़काव करने की सलाह विभिन्न देशों को दी है। कई देशों जैसे- चीन, पाकिस्तान आदि ने टिड्डियों को भगाने के लिये खेतों में बर्तनों को बजाना, फसलों पर विभिन्न रसायनों का छिड़काव, गाड़ियों के सायरन आदि के माध्यम से टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया था। भारत में भी टिड्डि दल के हमले को नियंत्रित करने के लिये लोगों द्वारा थाली बजाना, ड्रोन एवं अन्य माध्यमों से रसायनों का छिड़काव करना, कृषि क्षेत्र के आसपास गड्ढे खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल एवं केरोसीन के मिश्रण में गिराना आदि अनेक प्रकार के प्रयास किये गए।

भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिड्डियों के आपदा से निपटने के लिये अनेक प्रकार के कदम उठाए गए। टिड्डियों के आपदा को रोकने एवं इनके प्रभाव को कम करने के लिये सभी देशों को एक समेकित एवं सुनियोजित नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से इस आपदा को खत्म किया जा सके।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2002 से प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में आकाशीय बिजली सबसे बड़ा एकल कारण बना हुआ है। इससे होने वाली मौतों की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

According to the NCRB report lightning remains the single largest cause for mortality due to natural disasters in India since 2002. Highlighting the trend of such deaths, deliberate upon the steps taken by the government in this direction.

उत्तर: दुनिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से प्रतिवर्ष हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अन्य आपदाओं जैसे–बाढ़, सूखा या भूकंप की तुलना में बिजली से मरने वालों की संख्या अधिक होती है।

भारत में प्रतिवर्ष औसतन 2360 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मर जाते हैं। NCRB के आँकड़ों के पता चलता है कि 2002 के बाद से हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में बिजली सबसे बड़ा एकल कारण बनी हुई है। भारत में 2001 अब तक बिजली की चपेट में आकर 40 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी

तेज़ी से बदलते वक्त
और डिजिटल होती दुनिया के साथ
हम भी रख रहे हैं कदम,
पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन संसार में

Drishti Learning App

पर आपका स्वागत है

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव, टैबलेट मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।
- दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध डेली करेंट अफेयर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, क्विज़ तथा कई अन्य सुविधाएँ।
- हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल्स के सभी वीडियो वर्गीकृत रूप में उपलब्ध।
- टॉपर्स की उत्तर-पुस्तिकाएँ, एनसीइआरटी प्रश्नोत्तरी, हज़ारों अभ्यास प्रश्नों की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन, पेनड्राइव, एस.डी. कार्ड एवं टैबलेट मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

Quick Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Phone: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 280